

भारत की न्याय वतिरण प्रणाली में सुधार

परलिमिस् के लयि: भारतीय न्यायपालकि, सर्वोच्च न्यायालय, ई-कोर्ट परयोजना, राष्ट्रीय न्यायकि नयिकुतआयोग, लोक अदालतें, **FASTER**, न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, **ADR** तंत्र, मध्यस्थता, जनहति याचिकाएँ

मेन्स के लयि: भारत में न्यायकि बैकलॉग, भारतीय न्यायपालकि में न्यायकि सुधार, भारतीय न्यायपालकि से संबंधति वर्तमान प्रमुख मुद्दे, भारत में न्यायकि सुधारों से संबंधति प्रमुख पहल ।

स्रोत: द हदि

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामलों के भारी लंबति बोझ के कारण भारतीय न्यायपालकि गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, जसिसे न्याय वतिरण प्रणाली, सुशासन तथा कानूनी व्यवस्था में नागरिकों का वशिवास गहराई से प्रभावति हो रहा है ।

न्यायकि लंबति मामलों से जुड़े प्रमुख आँकड़े क्या हैं?

लंबति मामलों की संख्या	वर्ष 2025 के मध्य तक, भारतीय न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबति हैं, जनिमें से ज़िला न्यायालय 90% (4.6 करोड़+) मामलों का नपिटारा कर रही हैं, इसके बाद उच्च न्यायालय (63.3 लाख+) और सर्वोच्च न्यायालय (86,700+) का स्थान है ।
नपिटान असमानताएँ (आपराधकि बनाम सविलि मामले)	आपराधकि मामलों का नपिटारा तेज़ी से होता है तथा उच्च न्यायालय में 85.3% मामले एक वर्ष के भीतर नपिटा दयि जाते हैं । - इसके वपिरीत, ज़िला न्यायालयों में केवल 38.7% सविलि मामलों का नपिटारा एक वर्ष के भीतर होता है, जबकलिगभग20% मामले 5 वर्ष से अधिक समय तक लंबति रहते हैं । - भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मामलों की बढ़ती लंबति संख्या पर चतिा व्यक्त की और इसका कारण ज़मानत देने में ज़िला न्यायालयों में व्याप्त 'भय-जनति मानसकिता' को बताया ।

भारतीय न्यायालयों में मामलों की उच्च लंबति संख्या के प्रमुख कारण क्या हैं?

- न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात में कमी: न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात 10 लाख लोगों पर 15 न्यायाधीशों पर स्तरि बना हुआ है, जो वधिआयोग की 50 की सफिरशि से काफी दूर है ।
 - हालाँकि नचिली न्यायपालकि में महिलाओं की हसिसेदारी 38% है, लेकिन उच्च न्यायालयों में उनका प्रतनिधितिव मात्र 14% है ।
- बार-बार स्थगन (Adjournments): न्यायालय मामलों में बार-बार स्थगन से सीधे तौर पर न्यायकि लंबतिता में वृद्धि होती है, जो अनसुलझे मामलों का संचय है ।
 - न्याय प्रदान करने में यह देरी कानूनी प्रणाली में जनता के वशिवास को कमज़ोर करती है ।
 - दलिली उच्च न्यायालय में वलिंबति मामलों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि 70% मामलों में तीन से अधिक स्थगन हुए थे ।
 - यद्यपि स्थगन की सीमा तय करने की प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, फरि भी इन्हें प्राय: मंजूरी दे दी जाती है, जसिसे "तारीख पर तारीख" की संस्कृति विकसति होती है ।
- अल्पप्रयुक्त ADR: मध्यस्थता, पंचाट और सुलह जैसे ADR तंत्र, लंबति मामलों के बोझ को कम करने की क्षमता रखने के बावजूद, अब भी पर्याप्त रूप से उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं ।

- साथ ही, देशभर में सभी ADR तंत्रों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत, अद्यतन एवं वसितृत आँकड़ों की कमी के कारण इनके उपयोग और प्रभावशीलता की समग्र एवं राष्ट्रीय स्तर की तस्वीर प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है।
- **मुकदमेबाज़ी में वृद्धि: वधिकि जागरूकता और जनहति याचिकाओं (PIL) में वृद्धि** के साथ-साथ नरिधार मामलों के कारण भी मुकदमेबाज़ी में वृद्धि हो रही है।
 - लंबति मामलों में लगभग 50 प्रतिशत मामले सरकारी वभिगों से संबंधित हैं, जहाँ नरिणय में वलिंब और नयिमति अपीलें लंबति मामलों के बोझ को और बढ़ा देती हैं।
- **संरचनात्मक एवं प्रकरयागत बाधाएँ:** अपर्याप्त न्यायालय कक्ष, कार्मकिों की कमी, कमज़ोर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना, प्रकरण प्रबंधन प्रणालियों का अभाव, बार-बार स्थगन, गवाहों एवं साक्ष्यों में वलिंब।

भारत में न्यायकि सुधारों से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- **न्याय प्रदायगी और वधिकि सुधार के लिये राष्ट्रीय मशिन (2011):** न्याय तक पहुँच, दक्षता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपायों को लागू करना।
- **ई-कोर्ट परियोजना:** न्यायालयों का डिजिटलीकरण, जिसमें पेपरलेस फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और मामलों के शीघ्र नपिटारे की सुवधि शामिल है।
- **भारतीय राष्ट्रीय न्यायकि अवसंरचना प्राधकिरण:** देशभर में एक समान न्यायकि अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित संस्था।
- **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:** चुनदा प्रकार के मामलों के त्वरति सुनवाई एवं नपिटारे के लिये समर्पित न्यायालय।
- **वैकल्पिक वविाद नपिटान (ADR) तंत्र:** मुकदमेबाज़ी के तेज़ और कफायती विकल्प के रूप में मध्यस्थता, पंचाट और सुलह की सुवधि प्रदान करता है।
- **टेली-लॉ:** तकनीक के माध्यम से हाशयि पर स्थति लोगों को दूरस्थ कानूनी परामर्श से जोड़ता है।
- **न्याय बंधु (प्रो बोनो):** सवैच्छिक वकीलों द्वारा ज़रूरतमंदों को नःशुल्क वधिकि सहायता प्रदान करना।
- **न्यायकि रकिर्तियों की प्ररति:** वर्ष 2014 से 2024 के बीच सर्वोच्च न्यायालय में 62 तथा उच्च न्यायालयों में 976 न्यायाधीश नयिकृत कयि गए, जनिमें से 745 को स्थायी नयिकृति दी गई। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढ़कर 1,114 हो गई, जबकि ज़िला न्यायालयों में यह संख्या 19,518 से बढ़कर 25,609 हो गई, जो न्यायकि क्षमता बढ़ाने और लंबति मामलों को कम करने के प्रयासों को दर्शाता है।

वैकल्पिक वविाद समाधान तंत्र क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: [वैकल्पिक वविाद समाधान तंत्र](#)

भारत की न्यायकि प्रणाली को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय कयि जाने चाहयि?

- **न्यायकि क्षमता एवं नयिकृतियों को मज़बूत करना:** उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों में त्वरति नयिकृतियाँ करना तथा वर्ष 1987 के वधिआयोग की सफिरशि के अनुसार न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को 50 प्रतिमिलियन तक बढ़ाना।
 - कोलेजियम की पारदर्शति में सुधार, सेवानवृत्ति आयु में वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या में वसितार, और वशिषीकृत न्यायालयों का गठन।
 - **द्वितीय (ARC) के राष्ट्रीय न्यायकि परषिद के प्रस्तावों** को लागू करना, जिससे सरल वधिनों का नरिमाण, समयबद्ध सुनवाई, मामलों का शीघ्र नपिटारा, न्यायालयों का वसितार, तथा सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशकिषण का उन्नत उपयोग संभव हो सके।
- **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सुधार:** राष्ट्रीय न्यायकि अवसंरचना प्राधकिरण (NJIA) की स्थापना से न्यायालय सुवधियों का मानकीकरण कयि जा सकेगा।
 - **ई-कोर्ट परियोजना** के वसितार, **FASTER** जैसे उपकरणों के उपयोग, तथा कार्मकिों के नरितर प्रशकिषण से डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई, और वाद प्रबंधन की दक्षता में वृद्धि होगी।
- **प्रकरयात्मक एवं केस प्रबंधन सुधार:** स्थगनों की सीमा तय करना, संक्षिप्त मुकदमों को बढ़ावा देना, पूर्व-वाद सम्मेलन आयोजित करना, तथा समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना, इन उपायों से न्याय प्रकरया में तीव्रता लाई जा सकती है।
 - प्रभिषति समय-सीमा के साथ मामलों के वर्गीकरण, सूचीकरण और अनुवर्तन हेतु कृत्रमि बुद्धमित्ता (AI) उपकरणों का एकीकरण न्यायपालकि में दक्षता और पारदर्शति को सुदृढ़ करेगा।
- **ADR और वधिकि पहुँच को बढ़ावा देना:** मध्यस्थता, पंचाट और सुलह जैसे **वैकल्पिक वविाद समाधान (ADR) तंत्रों** का वसितार न्यायालयों का बोझ कम करने में सहायक हो सकता है।
 - **मध्यस्थता अधनियम, 2023** के प्रभावी करयान्वयन तथा लोक अदालतों का वसितार, जनिहोंने वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच 27.5 करोड़ मामलों का नपिटान कयि, न्यायालय के बाहर वविाद समाधान की संभावनाओं को रेखांकित करता है।
 - **टेली-लॉ, मोबाइल क्लीनिक** तथा **NALSA** की व्यापक पहुँच के माध्यम से नःशुल्क वधिकि सहायता को मज़बूत करना वंचति वर्गों के लिये न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करेगा।

नषिकरषः

भारतीय न्यायपालिका एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जहाँ सुधारों को परणामों में परिवर्तित करना आवश्यक है। न्याय में वलिब जन-वशिवास और संवैधानिक मूल्यों को नरितर क्षीण करता रहता है। वादों में नरितर वृद्धि और क्षमता के बीच के अंतराल को कम करना, ADR तंत्र को मज़बूत करना, तथा बुनियादी ढाँचे और प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना केवल नीतगत वकिल्प नहीं हैं, अपत्ति वधि के शासन को बनाए रखने और समय पर, सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक दायित्व हैं।

दृष्टभेन्स प्रश्नः

प्रश्न. न्यायिक लंबितता भारत की वधिक प्रणाली में गंभीर वकृत्तिके लक्षण हैं। लंबति मामलों की उच्च संख्या के लिये उत्तरदायी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बाधाओं का आलोचनात्मक वश्लेषण कीजिये तथा इस चुनौती से नपिटने के लिये व्यापक सुधारों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिये: (2019)

1. भारत के संवधिन के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के नरिवाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संवधिन के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभखिंडति कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतकिरण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधकिरण के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिये: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को नःशुल्क एवं सक्षम वधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश-भर में वधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य वधिक सेवा प्राधकिरणों को नरिदेश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नयुक्तिके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

प्रश्न. नःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? नःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतपिदन में राष्ट्रीय वधि सेवा प्राधकिरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिये। (2023)

